नॉर्दर्न जोन इन्श्योरेन्स एम्प्लोईज एसोसिएशन दिल्ली मण्डल समिति-1

39वे. त्रैवार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत प्रतिवेदन

साथी अध्यक्ष, साथी महासचिव, विशिष्ट अतिथिगण, प्रतिनिधि व प्रयवेक्षक साथियों

नार्दन जोन इन्शोरेन्स एम्पलाईज ऐसोसिऐशन दिल्ली मण्डल कमेटी -1 के 39 वे. अधिवेशन में उपस्थित आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। हम इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि साथी नवीन चन्द, महासचिव NZIEA, साथी अनिल कुमार भटनागर, उपाध्यक्ष AIIEA, का विशेषतौर पर स्वागत करते हैं। साथी अपनी तमाम सांगठनिक व्यवस्तताओं के बावजूद हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी नेतृत्वकारी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं।

हमारा पिछला अधिवेशन दिनांक 9-10 सितम्बर 2019 को दिल्ली में सम्पन्न हुआ था। पिछले तीन वर्षों में विश्व भारी उथल-पुथल के दौर से गुजरा और गुजर रहा है और कोरोना महामारी ने इस संकट को और गहरा कर दिया है।

जहां पूजी व मुनाफे बेलबाम बढ़े है वही मेहनत कर्श वर्ग की सुविधाओं पर हमले भी बढ़े है विश्व के पैमाने पर हमारी 70 प्रतिशत आबादी भुखमरी, अशिक्षा, शोषण, गरीबी, कुपोषण, युद्ध व आंतकवाद से पीड़ित है इसलिए पूरी दुनिया मे मेहनतकशो के सघर्ष भी तीव्र हुऐ है। हमारे देश मे भी मोदीनीत भाजपा सरकार अपनी तमाम कार्पोरेट हितैषी व आम जन विरोधी, नोटबन्दी, GST जैसे तमाम प्रतिकूल फैसलो के बावजूद दोबारा सता पर काबिज हुई और त्रासदी यह है कि इस बार अच्छे दिन, महंगाई, बेरोज़गारी, काले धन की वापसी, किसानो द्वारा आत्महत्यायें, शिक्षा जैसे मुददे ही गायब कर दिये। इस की जगह नैगम घरानों की घनबल से मदद तथा मीडिया के कुप्रचार से राष्ट्रवाद को हवा देते हुऐ जाति, धर्म व क्षेत्र पर आधिरत फूटपरस्त व भड़काऊ नारो का प्रयोग नेताओं द्वारा किया जाना एक दिनचर्या बन गया है।

विगत अधिवेशन से आज तक देश के आमजन, मेहनतकशो, बीमा कर्मियो व अपने संस्थान के हितार्थ संगठन के विभिन्न आह्वानो की शानदार अनुपालना व सागंठनिक उत्तरदायित्वो के पूर्ण निष्ठा के साथ किये गये निर्वहन से निखरकर व बेहतरीन वेतन पुनरीक्षण से प्रफुल्लित हमारे साथी अत्यन्त जोश व उत्साह के साथ इस सम्मेलन में शामिल होने आये है इस अधिवेशन मे हमारे संगठन से जुड़े कई नये साथी भी अत्यन्त जोश व उत्साह के साथ सम्मिलित हुऐ है जो कि

पहली बार हमारे ऐसे किसी अधिवेशन में हिस्सा ले रहे है।

साथियों हमारा यह स्पष्ट मानना है कि संगठन का अधिवेशन केवल औपचारिकता निर्वहन मात्र नहीं अपितु एक ऐसा अवसर है जिसके द्वारा हम संगठन द्वारा पिछले अधिवेशन से अब तक की समस्त राजनैतिक, आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्र में घटित घटनाओं व संगठन के कार्यो की विवेचना करते है और अपने भविष्य की नीति निर्धारित करते है। हमे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश व उद्योग के सामने उपस्थित चुनौतियों का सही व सटीक विश्लेषण कर यह सम्मेलन आने वाले समय का दिशा निर्देश तय करेगा।

हम प्रतिनिधि व प्रयवेक्षक साथियों से अपेक्षा करते है कि वे अनुशासन के साथ मण्डल स्तर की अपनी गतिविधियों का वर्णन करते हुऐ सांगठनिक मुददों पर सार्थक व उददेश्यपूर्ण चर्चा करेगें और प्रस्तुत प्रतिवेदन को सम्पूर्णता प्रदान कर आने वाले समय में संगठन को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने मे अपना योगदान देगें।

श्रद्धांजली

पिछले तीन वर्षों में हमने साहित्य, विज्ञान, रंगमंच, राजनीति, ट्रेडयूनियन तथा खेलजगत की अनेक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विभूतियों को खोया है। हम उन सब विभूतियों को भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित करते हैं। हम करोना महामारी से अकाल मौत के मुंह में जाने वाले लाखों लोगों को भी भरे दिल से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। विश्वशांति स्थापना हेतू जीवन बलिदान करने तथा शोषण के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी जान गंवाने वाले मजदूरों, छात्रों, आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं, सैनिकों, किसानों, नौजवानों तथा महिलाओं को भी हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध तथा आतंकवाद के हाथों अपनी जान गंवाने वालों को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

1. साथी के वेणुगोपाल राव – 30–04–2021 को बीमा कर्मियों ने एक प्रभावशाली बौद्धिक समीक्षक तथा शानदार वक्ता AIIEA उपाध्यक्ष साथी के वेणुगोपाल राव को खो दिया। बाईपास सर्जरी के बाद करोना संक्रमण ने साथी को हमसे छीन लिया। इंश्योरेंस वर्कर में साथी के लगातार लेख छपते थे जो उनकी प्रखर समझ को दर्शाते थे। हम साथी के वेणुगोपाल राव के निधन पर गहरा दु:ख जताते हुए उनके देश के जनवादी आन्दोलनों तथा संगठन को दिए गए उनके योगदान को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

2. साथी एन. के. पचौरी – AIIEA के पूर्व उपाध्यक्ष साथी एन. के. पचौरी का करोना संक्रमण से निधन हो गया। साथी एन. के. पचौरी के इंश्योरेंस वर्कर में लगातार हिंदी में लेख प्रकाशित होते थे। हम साथी के देश के ट्रेड यूनियन आन्दोलन तथा संगठन को दिये बहुमुल्य योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

3. EZIEA के भूतपूर्व महासचिव साईबल **चौधरी** – AIIEA की पूर्वी क्षेत्रों की इकाइयों को सुदृढ़ करने के बहुमुल्य योगदान को याद करते हुए हम साथी साइवुल चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

4. साथी एस. एस. कूनर – NZIEA के पूर्व अध्यक्ष साथी एस. एस. कूनर का निधन 15.12.2021 को हो गया। साथी कूनर एक निडर, उत्साही तथा महान वक्ता थे। 1974 में लाकडाऊन संघर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा किये गये निलम्बन भी साथी को संघर्ष के रास्ते से नहीं डिगा सका। उनकी कार्यशैली और संगठनात्मक प्रतिबद्धता हमें मार्गदर्शन देती रहेगी। हम साथी कूनर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

5. हम NZIEA के पूर्व मुख्य कोषाध्यक्ष साथी **रामेश्वर दयाल** का 13.04.2022 को निधन हो जाने पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। साथी **रामेश्वर दयाल** नें लम्बे समय तक संगठन में कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी और नॉर्दन जोन के Accounts के रख-रखाव में एक अहम भूमिका निभाई हम उनके सहयोग व योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रंद्धाजलि अर्पित करते हैं।

6. हम अजमेर मण्डल के पूर्व अध्यक्ष साथी दिनेश गौड़ व्यंग्याकार और वामपंथी विचारक के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

7. हम कला, रंगमंच व सिने जगत से जुडी हस्तियों लता मंगेशकर, डा. श्री राम लागू, शौकत कैफी आजमी, वीजू खोटें, श्याम रामसे, पदम भूषण खैयाम, राहत इंदौरी, कपिला वात्सायन, पंडित जसराज, एस.पी. बालासुब्रमणयम, अली जावेद, ऋषि कूपर, दलीप कुमार, सुशांत सिंह राजपुत, इरफान खान, सोमेत्रा चटर्जी, अभिलाष, शशिकला, राजीव कपूर, अरविन्द त्रिवेदी, उस्ताद मुस्तफा खान, नरेन्द्र चंचल, पुनीत राजकुमार, विरजू महाराज, भप्पी लहरी, सरोज खान, शिवकुमार शर्मा, गायक सिद्धु मूसेवाला और के.कृष्णा को अपने-अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

8. हम सीटू की प्रख्यात नेत्री रंजना नरूला के निधन पर उनके मजदूर वर्ग के संघर्षों खासकर महिलाओं के मुद्धों पर उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

9. हम राजनीति क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी, अजीत सिंह, कामरेड गौतम दास, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, कामरेड गुरूदास गुप्ता, अरूण जेटली, राजा वीरभद्र सिंह, पंडित सुखराम, रामविलास पासवान, अहमद पटेल, अजीत जोगी, अमर सिंह, कामरेड अरूण कुमार, कामरेड के. आर. गौरी अम्मा तथा जसवन्त सिंह के निधन पर शोक प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

10. हम सामाजिक कार्यकर्ता स्टेन स्वामी, पत्रकार कमाल खान, रोहित सरदाना, स्वामी अग्निवेश, पदमश्री विजेता विनोद दुआ, जनरल वी. एन. रावत, टी. एन. शेषण के निधन पर शोक प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

11. हम खेल जगत से जुड़ी हस्तियों क्रिकेटर यशपाल शर्मा, शेन वार्न, डीन जोंस, एन्ड्रयू साइमंड, प्रख्यात फुटवालर डियेगो माराडोना, हॉकी खिलाड़ी कृष्ण कौशिक, रविन्द्रपाल सिंह, टैनिस

खिलाड़ी अखतर अली, अर्जुन आवर्डी वी. चन्द्रशेखर तथा मशहूर धावक मिल्खा सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

हम अमर नाथ यात्रा के दौरान मारे गये श्रदालुओ, किसान आन्दोलन में शहीद हुऐ किसानों की शहादत को याद करते हुये उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ पैंशनर्ज साथी भी हमसे बिछुड गये। हम उन्हें भी इस अधिवेशन के माध्यम से श्रद्धाजंलि अर्पित करते है। हम उन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धाजंलि अर्पित करते है जिनके नाम हम यहां शामिल नहीं कर पाये।

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति

पिछले अधिवेशन के बाद की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इस प्रकार रही है।

(1) कोविड महामारी : 2019 मे फूटी महामारी अब दुनिया भर मे एक बड़ा मुददा है इसका कहर अब भी जारी है कोरोना वायरस तेजी से खुद को बदल रहा है उसके नये–2 वेरिएंट आ रहे है इसके ओमिक्रोन वेरिएंट से 30 करोड़ लोग प्रभावित हुए और 55 लाख से ज्यादा लोगो ने अपनी जान गवांई। जब तक सार्वभौम वैश्विक कार्यक्रम के जरिए टीकाकरण की मुहीम तेज नही होती है महामारी तबाही बरपा करती रहेगी। टीका असमानता ही नये वेरिएंटो को पैदा कर रही है। उच्च आय श्रेणी वाले देशो मे करीब–2 टीकाकरण हो चुका है। जबकि कम आय वाले देशों मे यह दर बहुत ही कम है।

इस महामारी में पूंजीवाद के अर्न्तगत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दयनीय रूप से अप्रयाप्त होने को उजागर किया है। मुनाफे अधिकतम करने की नवउदारवादी नीतियों के चलते स्वास्थय सुविधाओं का बड़े पैमाने पर निजीकरण हुआ है। टीकाकरण असमानता के साथ इसका भी जनता की जिन्दगियों पर खासतौर पर गरीब और विकासशील देशों मे तबाह करने वाला असर हुआ है। क्यूबा ने क्रूर अमरीकी नाकेबंदी के चलते भारी आर्थिक मुश्किलो का सामना करते हुए बाहर से दवाओं और उपकरणो को मंगाने पर रोक के बावजूद अपने घरेलू टीकों का विकास किया और दुनिया मे 50 से ज्यादा देशों में अपने मेडिकल मिश्न भेजे, जिसमे टीकों की आपूर्ति भी शामिल है।

वैश्विक **पूंजीवाद संकट :** 2008 के वैश्विक वित्तिय महाझटके से उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के बाद से वैश्विक पूंजीवाद पहले वाले स्तर तक नही पहुंच पाया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुसार महामारी आने से पहले वैश्विक जी.डी.पी. वृद्धि 2009 के 5.4% से लगातार गिरते हुए 2019 मे 2.9% रह गई। महामारी से जुड़े लॉकडाउन व उत्पादन बंदी के चलते, 2020 मे विश्व अर्थव्यवस्था में 4.4% का सकुंचन हुआ। विश्व बैंक इस पर कायम है कि 2022 मे विश्व उत्पाद, महामारी के पहले के विश्व उत्पाद के अनुमानो से 2% नीचे रहेगा।

बढ़ती असमानताएं : अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के वैश्विक उत्पाद के आशावादी अनुमान बहुत हद तक, अमेरिका तथा युरोपिय युनियन मे घोषित नये उत्प्रेरण पैकेजो से पैदा हुई आर्थिक

बहाली की उम्मीदों पर आधारित है। अमेरिका ने 19 अरब डालर के पैकेज का ऐलान किया जबकि युरोपिय युनियन ने 18 अरब यूरो (22 खरब डालर) के पैकेज के सहमति दी। इस पैकेज से मेहनतकश जनता व मध्य वर्ग को सीमित प्रत्यक्ष लाभ मिले है जबकि बड़े पूंजीपतियों को ही असली उपहार मिला है। उत्प्रेरक पैकेजो की वित्त व्यवस्था ने ही शेयर बाजार के उछालों को भड़काया है और असमानताओं को जन्म दिया है। विश्व अरबपत्तियों की कुल सपंदा 2020 जुलाई में 102 खरब डालर के नये शिखर पर पहुंच चुकी थी। 10 सबसे धनी लोगों की सम्पदा में पिछले वर्ष 413 अरब डालर की वृद्धि हुई जो कि 2021 के लिये सयुक्त राष्ट्रसंघ की समूची मानवतावादी अपील के लिये आवश्यक कुल राशी से 11 गुना ज्यादा थी। कोविड़ टीका बनाने वाले बड़े दवा निर्माताओं ने ही 9 नये वैश्विक अरबपति पैदा किये।

भुखमरी की समस्या और जनता की तकलीफे: आक्सफेम की रिपार्ट के अनुसार विश्व में हर मिनट 11 लोग भूख से मर रहे है। युनिसैफ के आकंलन के अनुसार वैश्विक आबादी का दसवां हिस्सा लगभग 81.1 करोड़ लोग कुपोषित हैं। 2020 मे 15 करोड़ बच्चे अवरूद्ध विकास वाले और लगभग 4.5 करोड़ दूसरे बच्चों की असमय मौत हुई। पिछले वर्ष 2021 में CRONIC अत्यधिक भूखमरी का सामना कर रहे करीब 18 करोड़ लोगों को मिलाकर आबादी के 30% यानी 237 करोड़ लोगों को प्रर्याप्त खाना हासिल नही था यह एक वर्ष मे 32 करोड़ की बढ़त है।

अंत चरम गरीबी मे जीते हुए लोगों की संख्या 2021 के अतं तक 74.5 करोड़ के लगभग है जो 10 करोड़ बढ़ी है पूरी दुनिया में महिलाओं के रोजगार छिनने से उनकी आमदनी मे कम से कम 80,000 करोड़ डालर की कमी आई है।

मुनाफे बढ़ाने के नवउदारवादी झुकाव ने एक दीर्घ पूंजीवादी संकट के हालात तैयार किये है क्योंकि वे कामगार जनता के आर्थिक शोषण पर काम करते है। 2008 से जारी संकट और मंदी के कारण इग्लेंड, इटली, जापान आदि विकसित देशों में वास्तविक वेतन में गिरावट आई। 2008 से Cost Cutting के उपायों के चलते श्रम की उत्पादकता (21.8%) बढ़ी जबकि इसके मुकाबले वेतन वृद्धि केवल 14.3% रही। 2019-2020 के बीच नौकरियां छिनने की बढ़ती दर के साथ वैश्विक श्रम आय में 10.7% की गिरावट आई जो कि 3.5 ट्रिलियन डालर के बराबर है। 2021 में हालात और भी बदतर हुए हैं।

शिक्षा : युनेस्कों के अनुसार महामारी के दौरान दुनिया भर के 90% बच्चों की शिक्षा बाधित हुई। हालात यह थे कि 26 देशों में विधालय पूरी तरह बंद थे। जबकि 55 अन्य देशों में आंशिक रूप से बंद थे। आर्थिक तंगी के चलते बच्चों को मजबूरी में काम करना पड़ा है और शिक्षा से दूर हो गये है।

दक्षिण पंथ की और राजनैतिक झुकाव : दक्षिण पंथी ताकतें भावनात्मक जुनून को भड़काते हुए, विभाजनकारी नारे उछालते हुए नस्लवाद, अंध-राष्ट्रवाद, धार्मिक संकीर्णता को बढ़ावा देते हुए कामगार जनता के संगठित एकजुट-विरोध मुहीम को सशक्त होने से रोकने की कोशिश करती है इनके जरिए वे बढ़ते शोषण के खिलाफ जनता की एकता को ध्वस्त करना चाहती है।

बढ़ते विरोध प्रदर्शन : महामारी से पहले के आर्थिक संकट, उसके परिणामस्वरूप लागू Cost Cutting के उपायों, शोषण में आई तीव्रता के खिलाफ और महामारी के दौरान थोपी गई विपदाओं, तालाबंदी और जनकल्याण के नाकाफी प्रावधानों के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ गया है। महामारी के बावजूद दुनिया के कई हिस्सों में विरोध प्रर्दशन हुए हैं। इस तरह के विरोध प्रर्दशन अमेरिका में सबसे अधिक मुखर थे, वही अर्जेन्टीना, ब्राजील, कोलम्बिया, चिली, इकबाडोर, मेक्सिको और उरूग्वे आदि देशों में कामगार जनता ने हड़तालें और बड़े प्रर्दशन आयोजित किये।

युरोप के औद्योगिक कामगार व सेवा क्षेत्र में काम करने वाले डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक आदि हड़ताल पर गए। फ्रांस में श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ विरोध प्रर्दशन हुए और बढ़े हुए टैक्स बोझ के खिलाफ 'येलो वेस्टस' की जुझारू कार्यवाही हुई। अन्य देशों में भी श्रम कानूनों के खिलाफ संघर्ष चल रहे हैं।

रूस-युक्रेन युद्ध - इस वर्ष फरवरी में शुरू हुए युद्ध ने अब तक भारी तबाही मचाई है। लाखों लोग युक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर गये हैं। युक्रेन के युरोपिय संघ व नाटो की सदस्यता को रूस ने अपनी सुरक्षा को गंभीर खतरा माना। इस स्थिति के लिये अमेरिका व युरोप भी जिम्मेवार हैं क्योंकि रूस के विघटन के बाद पूर्वी युरोप में नाटो अपना विस्तार करना चाहता था। रूस द्वारा इस पर आपत्ति को नाटो ने नहीं माना। अब विश्व बिरादरी के दोनों पक्षों को बातचीत से कोई रास्ता निकालना होगा ताकि दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखा जा सके।

इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया दो हिस्सों में बट गई। नाटो के समर्थक व रूस के

समर्थक। यह लड़ाई अब जमीन, जल से ऊपर अंतरिक्ष में पहुंच गई है। अमेरिका सहित कई देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिये हैं। इसके दूरगामी परिणाम पूरे विश्व को प्रभावित करेगें। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी प्रमुख ने अमेरिका को धमकी दी है कि मास्को पर लगाए प्रतिबंध अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर दोनों देशों के बीच सहयोग खत्म कर सकते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (NASA) भी इस अंतरिक्ष स्टेशन में रूस को मिल रहे सहयोग खत्म करने की तैयारी में हैं।

श्री लंका में जनशक्ति की जीत : श्री लंका में 9 जुलाई को बड़े नाटकीय ढंग से हजारों लोगों ने राष्ट्रपति के महल, सचिवालय और प्रधानमंत्री के आवास पर धावा बोल दिया। सुरक्षा व्यवस्था को खदेड़ उस पर कब्जा कर लिया।

देशभर के नागरिक जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, कोलम्बो पहुचें, ताकि राष्ट्रपति गोटबाया तथा राजपक्षे खानदान के तानाशाही भ्रष्ट शासन का खात्मा हो सके।

यह संघर्ष गत 31 मार्च को तब शुरू हुआ जब समाज के हर तबके के लोग, देश में व्याप्त आर्थिक संकट, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों की कमी हो गई थी, ईंधन नही मिल रहा था और महंगाई आसमान छूने लगी थी, के खिलाफ इकट्ठे हुए।

जैसे ही श्री लंका में अर्थव्यवस्था ठप्प हुई, विदेशी ऋण चुकाने के मामले में देश दिवालिया हो गया। यह शांतिपूर्ण विरोध प्रर्दशन 'गोटा गो गाम' (गोटा घर जाओ) के नारे के साथ आन्दोलन में तबदील हो गया।

वर्ष 2019 में गोटबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, श्री लंका के संविधान में 20 वां संशोधन किया गया, इसमें राष्ट्रपति को न्यायधीशों की नियुक्ति पर नियंत्रण और चुनाव आयोग, पुलिस आयोग तथा घूसखोरी व भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग पर नियंत्रण शामिल है तथा प्रधानमंत्री के रूप में उनके भाई महेन्द्रा राजपक्षे के साथ परिजनों को प्रमुख मंत्रालयों तथा पदों पर नियुक्त किया। देश के बजट का कुल 75 प्रतिशत हिस्सा सीधे राजपक्षे के करीबी मंत्रियों के दायरे में आता था। मौजूदा आर्थिक संकट सिर्फ अर्थव्यवस्था कुप्रबन्धन और गलत नीतियों के चलते ही नहीं आया बल्कि भ्रष्टाचार भी इस के लिए जिम्मेवार है।

श्री लंका की जनता के लिए संकट अभी खत्म होने वाला नहीं है लेकिन जनता ने जो हासिल किया वह तानाशाह निजामों के लिए एक चेतावनी है जो राष्ट्रवाद और साम्प्रदायिक

धुव्रीकरण पर ही फलते फूलते हैं। चाहे आप कितने भी स्थाई व मजबूत नजर आते हों लेकिन लोग हमेशा दास बनकर रहने वाले नहीं हैं, कभी न कभी क्रांति आयेगी और बदलाव आयेगा।

जलवायु परिवर्तन के खतरे : गत वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में काफी तेजी आई है। यह एक वर्गीय मुद्दा है, पूंजीवाद द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की अनियंत्रित लूट है जिसने भयावह हालात पैदा किये हैं। अगस्त 2021 में जारी Inter Governmental Penal on Climate Change की ताजा रिर्पोट में पहली बार कहा गया है कि जलवायु संकट पैदा करने वाले वायुमण्डलीय ग्रीन हाउस गैस कन्सेन्ट्रेशन का एकमात्र कारण मानवीय गतिविधियां हैं। भूमण्डलीय औसत तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के मौजूदा स्तर पर भी इस साल पूरी दुनिया ऐसे जलवायु प्रभावों की साक्षी रही जो अपनी प्रचण्डता और स्तर के लिये जाने गए। यह खासकर उत्तरी गोलार्द में देखा गया। पता चला कि 1.5 से 2 सेलसियस की तापमान बढ़त कितनी भयावह हो सकती है। भारत भी वार्षिक स्तर पर अतिवृष्टि का साक्षी रहा जिसके कारण भूस्खलन, बाढ़ और जलभराव बड़े पैमाने पर हुए।

राष्ट्रीय परिस्थिति :

मोदी सरकार के करीब 8 साल एक दक्षिणपंथी, तानाशाहीपूर्ण–साम्प्रदायिक निजाम ले आए हैं : नवउदारवादी नीतियों पर तेजी से चलते, जिसके चलते मेहनत कश जनता पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। आर एस एस के हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने के सतत् प्रयास , जिससे शासन के धर्म निरपेक्ष, जनतांत्रिक ढाचें के लिए खतरा पैदा हो गया है तथा इसके साथ रणनीतिक गठजोड़ को मजबूत करना तथा एक अधीनस्थ सहयोगी की भूमिका अदा करना और संसदीय जनतंत्र को कतरने तथा संवैधानिक संस्थाओं तथा जनतांत्रिक अधिकारों को ध्वस्त करने के जरिए, तानाशाही का ढांचा खड़ा करना ही इस सरकार का उद्देश्य बन गया है।

मोदी सरकार के पुनः सत्तासीन होने के पश्चात् दक्षिणपंथी हमला और तेज हुआ है। बहरहाल, पहली बार से ज्यादा सीटों तथा मत फीसद के साथ दोबारा सत्ता में आने के पश्चात्, के हिंदुत्व के एजेंडे को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाया जाना शुरू हो गया है। खासतौर पर 2019 में कोविड के सामने आने के बाद में जो कुछ सामने आ रहा है, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रियावादी पार्टी है, जिसका ऐसा फूटपरस्त तथा साम्प्रदायिक मंच है, जिसकी सोच अन्य धर्मों के प्रति घृणा,असहिष्णुताऔर अन्धराष्ट्रवादी उन्माद पर आधारित है। भाजपा के सत्ता में रहने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहुंच सरकारी मशीनरी और राज्य तंत्र के विभिन्न अंगों तक हो गई है जो कि हिंदुत्व की विचारधारा, पुनरूत्थानवाद को बढ़ावा देती है तथा एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना का लक्ष्य लेकर भारत की मिली–जुली संस्कृति को ठुकराती है।

साम्प्रदायिक और फासीवादी सोच वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व वाले गठबंधन के उभार और उसके केन्द्र में सत्ता संभालने के साथ धर्मनिरपेक्ष बुनियाद के लिए पैदा हुई चुनौती ने एक बड़े खतरे का रूप ले लिया है। राज्य की संस्थाओं, प्रशासन, शिक्षा प्रणाली और सूचना माध्यमों में साम्प्रदायिकीकरण की योजनाबद्ध कोशिशे जारी हैं।

भाजपा एक बृहत्तर 'हिन्दू पहचान' गढ़ने में कामयाब रही, जो उल्लेखनीय हद तक सामाजिक–एथनिक विभाजनों के पार जाती थी और उसके साथ ही उसने निचले स्तर पर घोर जाति–आधारित गोलबंदियां खड़ी की। दौलत की बेशुमार ताकत और आर.एस.एस. भाजपा के मीडिया तथा सोशल मीडिया पर नियंत्रणों ने चुनाव नतीजों को उल्लेखनीय हद तक प्रभावित

किया भाजपा का यह धनबल, जिसे चुनावी बाँड के उपकरण समेत तरह-तरह से जमा किया गया है, विपक्ष को बराबरी के मैदान से वंचित करता है, जोकि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है।

2019 के चुनावी नतीजे, दक्षिपंथी की ओर राजनीतिक झुकाव के और उसके सुदृढ़ीकरण के और भारत में बढ़ते फासीवादी रूझानों के सूचक थे।

2019 के बाद से भाजपा सरकार :

दूसरी बार सत्ता संभालने के फौरन बाद, भाजपा सरकार ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा भंग कर दिया, संविधान की धारा-370 तथा 35-ए को निरस्त कर दिया, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती थी और दो केंद्रशासित क्षेत्र बना दिए।

इसके बाद सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून(CAA) बनाया और ऐलान कर दिया कि पहले राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर(NPR) बनाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार किया जाएगा। यह हमारे संविधान का घोर उल्लंधन है, जोकि नागरिकता को धर्म से नहीं जोड़ता है। CAA मुसलमानों को छोड़कर, दूसरे सभी विदेशी प्रवासियों को, नागरिकता देने को फास्ट-ट्रेक करने का प्रावधान करता है। इस सरासर असंवैधानिक कानून को दी गयी कानूनी चुनौतियां तीन साल होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने लम्बित है।

भारतीय संविधान के चरित्र को ही बदलने के सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय संविधान के चारों बुनियादी स्तंभों-धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, संघात्मक व्यवस्था, सामाजिक न्याय और आर्थिक संप्रभुता पर हमले हो रहे हैं।

आर्थिक संप्रभुता को कमजोर किया जाना :

2019 में दोबारा भाजपा सरकार बनने के बाद से नवउदारवादी आर्थिक सुधारों ने तेजी पकड़ ली है। भारतीय आर्थिक संप्रभुता का विनाश बहुआयामी तरीके से हो रहा है जो सामान्य निजीकरण तथा कॉपोरेटों को कर रियायतें दिए जाने से आगे तक जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से तथा विशेष रूप से प्रतिरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से, भारत की आत्मनिर्भरता की जो नीवें डाली गई थीं, उन सभी को कमजोर किया जा रहा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को दूसरों पर आश्रित बनाकर छोड़ देने की खतरनाक दिशा में ले जा रहा है।

हमारी राष्ट्रीय परिसम्पतियों तथा अर्थव्यवस्था के इस विनाश तथा लूट का, करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी पर बहुत भारी कुप्रभाव पड़ रहा है और इसके साथ ही यह अर्थव्यवस्था को अनवरत मंदी तथा संकट की दलदल में धकेल रहा है।

बजट 2022-23

वैसे तो वर्तमान सरकार के पिछले सभी बजट में आम जनता के साथ धोखा किया गया है। इनके बजट में मेहनतकश जनता की बदहाली की कीमत पर मुट्ठीभर बड़े व्यापारिक घरानों के हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश होती रही है। वर्ष 2021-22 के बजट में भी सरकार ने जन सरोकार से मुँह मोड़कर सार्वजनिक खर्चे बढ़ाने से इंकार कर जनता के साथ विश्वासघात किया था और वर्ष 2022-23 का बजट भी बेरोजगारी, मंहगाई तथा आय में कटौती से जूझ रहे बहुतायत जनता के मुद्दों को हल करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। आज के राष्ट्रीय आर्थिक हालात की पृष्ठभूमि में जरूरत इस बात की थी कि बजट में रोजगार निर्माण को और घरेलू मांग को बढ़ाने का प्रवाधान किया जाता, इसके विपरीत बजट में मनरेगा के लिए खर्चें में 25000 करोड़ रूपए की कमी कर दी गई। खाद्य, ईंधन उर्वरक सब्सीडियों तथा स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास के लिए आबंटनों को घटा दिया गया है। बजट से कुल खर्च में 2021-22 के संशोधित अनुमानों से रू0 1,74,909 करोड़ की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन जीडीपी के अनुपात के रूप में कुल खर्चे में बढ़ौतरी 2020-21 के 17.8 प्रतिशत के स्तर से घटकर 2022-23 के बजट अनुमान में 15.3 प्रतिशत ही रह गई है। राजस्व प्राप्तियों में हो रही बढ़ौतरी तथा पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के जरिए प्राप्त राजस्व के मुकाबले कुल खर्च काफी कम हैं और वास्तविक मूल्य के हिसाब से पिछले साल के संशोधित अनुमानों में हुई बढ़ौतरी से भी कम है। राज्यों के लिए संसाधनों के हस्तांतरण को घटाकर राज्यों को भी खर्च में कटौती करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। किसानों के लिए सभी प्रमुख योजनाओं में कटौती कर दी गई है। कृषि के लिए 2021-22 (संशोधित अनुमान में, कुल आबंटन 4,74,750.47 करोड़ रूपए का था जो अब घटकर 3,70,303 करोड़ रूपए कर दिया गया है जोकि 1 लाख करोड़ से अधिक की कमी है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा तथा विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अर्न्तगत खरीदी के लिए आबंटन में करीब 28 प्रतिशत की कमी कर दी गई है। उर्वरक सब्सिडी के लिए आबंटन में 25 प्रतिशत की कटौती की गई है। यह कमी उस वक्त की गई है जब किसान अपनी फसलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए संर्घषरत्त हैं। पी0एम0 किसान योजना के तहत

12.5 करोड़ किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रू0 देने के लिए 75000 करोड़ रू0 के आबंटन की जरूरत थी लेकिन इसके लिए 68000 करोड़ रूपयों का आबंटन किया गया है। फसल बीमा के आबंटन में भी करीब 500 करोड़ रूपये की कटौती की गई है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण फंड के लिए आबंटन में मामूली सी बढ़ौतरी की गई है, लेकिन मुद्रास्फीति के मद्देनजर यह नाकारत्मक है। इसके बावजूद कि पिछले साल 35 प्रतिशत बच्चों को दोपहर का भोजन नहीं मिला था। इस बार पी0एम0 पोषण योजना के आबंटन में कोई बढ़ौतरी नहीं की गई। 2 लाख आंगनवाड़ी को स्वावलम्बी बनाने के लिए नारीशक्ति की दूहाई जरूर दी गई लेकिन इसके लिए आबंटन को संशोधित अनुमान के 20,000 करोड़ रूपये के स्तर पर ही रखा गया है। पिछले दो साल में रसोई गैस सब्सिडी में भारी कटौती की गई है। कि अब गैस सब्सिडी का नामों निशान ही खत्म हो गया है ई-श्रम पोर्टलों के जरिए रजिस्टर किए गये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बजट में कोई आबंटन नहीं रखा गया है।

महामारी के दो वर्षों में अमीर और अमीर हो गए। सबसे ऊपर के पायेदान पर आने वाले 10 प्रतिशत लोगों के हाथों में भारत की कुल सम्पदा का 57 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बावजूद इसका कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है कि इन बेहिसाब मुनाफों पर अतिरिक्त कर लगाया जाए और इससे आने वाले संसाधनों का उपयोग बदहाल जनता के विशाल बहुमत को राहत देने के लिए किया जाए।

नेशनल ऐसटमोनेटाईजेशन पाइपलाइन के तहत (NAMP) सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित पूरे ढांचे का निजीकरण करने की सरकार की योजना इस बजट से साफ दिखाई देती है। भारत के बीमा उद्योग के लिए सरकार द्वारा बीमा उद्योग के निजीकरण की अपनी वचनबद्धता को अमली जामा पहनाते हुए LIC में I.P.O. लाकर इसमें विनिवेशीकरण का कार्य आरम्भ हो चुका है। अतः यह कहना सही होगा कि यह बजट पूरी तरह से परो-कॉरपोरेट है और देश के सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करने की ओर सरकार का कदम है।

बेरोजगारी

आर्थिक संकट से देश का एक बड़ा वर्ग बुरी तरह से प्रभावित है। नोटबंदी और अपरिपक्व तरीके से लागू की गई GST ने वैसे ही देश के अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) को बुरी तरह से तबाह कर दिया था, कोविड-19 महामारी और लॉकडाऊन ने इसे पूरी तरह से तबाह करने का

काम किया है। चूंकि अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) भारत में 90 प्रतिशत से अधिक लोगों को रोजगार देता है इसलिए इस कारण से बेरोजगारी में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है।

बढ़ती मंहगाई

देश की बढ़ती मुद्रास्फीति भी एक बड़ी चुनौती है। पैट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा बढ़ती मूल्यवृद्धि ने मंहगाई की आग में घी डालने का काम किया है। ज्यादा से ज्यादा राजस्व अर्जित करने की सोच के चलते पैट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स कम करने की मांग को सरकार द्वारा पूरी तरह से अनसुना किया जा रहा है।

इस वक्त मंहगाई देश में अपने चरम स्तर पर है। बीते 12 महीने से थोक मंहगाई का आंकड़ा दोहरे अंकों में बना हुआ है। इससे स्वाभाविक ही लोगों की रोजमर्रा की जिदंगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पहले ही लोगों की आमदन घट चुकी है। लाखों लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। जिस पर मंहगाई में उन्हें परिवार चलाना, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पर खर्च करना भारी पड़ रहा है। मगर कहीं से भी सरकार का रूख इस पर काबू पाने का नहीं दिखता। सरकार पिछले आठ सालों में पैट्रोल-डीजल पर साढ़े छब्बीस लाख करोड़ से अधिक की राशि आम जनता से कर के रूप में वसूल चुकी है। आज जब जनता संकट में है तो सरकार की दरियादिली दिखाने की बारी है। लेकिन अफसोस कि ऐसा कोई संकेत फिलहाल नहीं दिख रहा है।

शिक्षा

शिक्षा को सबकी पहुंच के भीतर बनाने की बजाए इसका व्यवसायीकरण कर दिया गया है। निशुल्क शिक्षा को सामाजिक स्तर पर गरीब और पिछड़े वर्ग तक सीमित रहने दिया गया है और उस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो गया है। इस सरकार के कार्यकाल में प्राथमिक विद्यालयों में 9 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। कालेजों और विश्वविद्यालयों में लगभग 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, फिर भी मोदी सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार ने बिना संसद में प्रस्तुत किए संवाददाता सम्मेलन में 'नयी शिक्षा नीति 2020' का जोर-शोर से प्रचार किया, जिसके तहत विश्वविद्यालयों को अपने केन्द्र खोलने की अनुमति देना, शिक्षा परिषदों और कार्यवाही परिषदों के स्थान पर बोर्ड ऑफ गवर्नैन्स बनाना और उन्हें फीस और शिक्षा पाठ्यक्रमों को तय

करने की स्वायत्तता देना और अनुदान मंडल द्वारा वित्त पोषण के स्थान पर ऋण प्रदान करना आदि प्रमुख है, जोकि गरीबों को उच्च शिक्षा की पहुंच से बाहर कर देगा।

किसान विरोधी काले कानून

2020 संसद के मानसून सत्र में केन्द्रीय सरकार ने जबरन तीन कृषि कानून पास किये। इन तीन कृषि कानूनो के बारे में सरकार का आज भी यही कहना है कि यह कानून किसानो के हितो के लिए बनाये गये हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अपने कारपोरेट मित्रों को सस्ते मे उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के निजीकरण के कदम, बुनियादी ढाँचा सम्पत्ति और रक्षा आयुद्य कारखाने के निगमीकरण के मार्ग पर नजर रखते हुऐ यह सरकार कृषि क्षेत्र के तीन कानून लाई।

इन कृषि कानूनो के विरूद्ध किसान संगठनों ने सयुँक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक बड़ा आन्दोलन चलाया। आजाद हिन्दुस्तान में यह पहला मौका था जब देश के किसानों को दिल्ली मे आने से रोकने के लिय पूरी दिल्ली को ही छावनी बना दिया गया। इन आन्दोलनरत किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिय हरियाणा की भाजपा सरकार ने पूरे हरियाणा में जगह-जगह नाके लगा कर रोकने की कोशिश की। दिल्ली बार्डर तक पहुचँने मे किसानों को पुलिस व सैन्य बलो की लाठियों, आंसू गैस के गोलो व पानी की बोछारो का सामना करना पड़ा लेकिन किसान अपने संघर्ष से डिगे नही अंततः दिल्ली की सीमाओं तक पहुचें और खराब मौसम, सबसे खराब गालियों, मानहानि, आरोपो और उकसावे का सामना करते हुऐ एक साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहें और इस दौरान उन्हें समाज के सभी वर्गो का समर्थन व सहयोग मिला।

लगभग एक साल चले इस आन्दोलन में 700 के लगभग किसान शहीद हुऐ लेकिन इस सब के बावजूद मजबूत एकता के साथ देश भर के किसान सरकार के खिलाफ डटे रहे जब सरकार को किसान आन्दोलन अपने गले की फांस बनता नजर आया तो प्रधानमन्त्री ने तीनों कृषि कानूनो को निरस्त करने को घोषणा की लेकिन सयुँक्त किसान मोर्चा ने अपने संघर्ष की पहल को कम नही होने दिया और 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप मे मनाया क्योंकि सरकार किसानो के आन्दोलन को खत्म करने से पहले दिये गये लिखित आश्वासन को लागू नही कर रही हैं।

साथियों यह मजदूर किसान एकता निश्चय ही संघर्ष के दौर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है यह सफल ऐतिहासिक संघर्ष सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ व बेहतर जीवन के लिय अपने संघर्षो मे जन मानस के सभी तबको को प्रेरणा देता रहेगा। **संघर्ष की जीत निश्चित है यह किसान आन्दोलन की हम सब कि लिए प्रेरणा व सीख है।**

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय परिस्थिति का आंकलन करने पर हम यह कह सकते हैं कि इन 3 वर्षों में देश की वर्तमान सरकार ने उन्हीं उदारवादी नीतियों जैसे FDI, विनिवेशीकरण, निजीकरण को आगे बढ़ाया है, जिनका विरोध करके वो सत्तासीन हुई थी। प्रगति और खुशहाली के तमाम पैमानों पर भारत की स्थिति चिंताजनक है। Global Hunger Index में भारत 116 देशों में पाकिस्तान बंगलादेश और नेपाल से भी पीछे है। Human Development Index में भारत 189 देशों में 131वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 105वें स्थान पर है और बंगलादेश 101वें स्थान पर है।

इन पिछले 3 वर्षों के दौर में हमने देखा कि किस तरह से वर्तमान सरकार ने देश की नियामक संस्थाओं को और अप्रासंगिक करने का कार्य किया है। प्रवर्तन निदेशालय और सी.बी.आई. का दुरूपयोग और आर.बी.आई. की स्वायत्तता पर जिस तरह हमले किये जा रहे हैं और जिस तरीके से उनका इस्तेमाल करके अपने ऐजेंडा को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, वह बेहद खतरनाक और तानाशाही की तरफ ले जाने वाला है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा के नाम पर ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले और जन विरोध को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

हमारा उद्योग

साथियों पिछले लगातार 65 वर्षों से भा0जी0नि0 की उन्नति को देखते हुए हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है और ये सब अचानक या एकदम से नहीं हुआ, इसके पीछे हमारे महान संगठन AIIEA की दूरगामी सोच एवं संघर्ष का इतिहास है।

साथियों 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तब देश की जनसंख्या 345 मिलियन और प्रति व्यक्ति आय केवल 249 रू0 थी और देश की साक्षरता दर केवल 12 प्रतिशत थी हमारे देश की गिनती गरीब देशों में की जाती थी। देश के इन सब हालात के मद्देनजर तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नहेरू ने देश की जनता की सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान एवं लघु बचत को बढ़ावा देने के लिए जीवन बीमा का विस्तार करने का मन बनाया, तब 1956 में भा0जी0बी0नि0 का जन्म हुआ और आज 2022 के वर्ष तक लगभग 65 वर्षों से अपना विश्वास बनाये हुए है। आज भा0जी0बी0 40 लाख करोड़ का Value Assest रखती है, जोकि देश के Mutual Fund के Asset Under Management (AUM–बाजार मूल्य) के बराबर है।

आज भा0जी0बी0नि0 के पास लगभग 31 करोड़ पोलिसीधारक हैं। 13.5 लाख से अधिक बीमा ऐजेन्ट हैं। यही नहीं आज भा0जी0बी0नि0 देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कम्पनी और दुनिया की पांचवी बड़ी जीवन बीमा कम्पनी है। आज भी देश में बिकने वाली हर चार बीमा पॉलिसी में से तीन भा0जी0बी0नि0 की होती हैं। आज भा0जी0बी0नि0 की नवव्यवसाय की हिस्सेदारी 68 प्रतिशत और मार्केट शेयर 76 प्रतिशत है। इसके अलावा भा0जी0बी0नि0 के पास लगभग 3400 सूक्ष्म बीमा ऐजन्ट हैं, जो देश की गरीब एवं मजदूर तबके में सस्ता बीमा बेचते हैं और गरीब लोगों को सस्ती बीमा सुरक्षा प्रदान करते है। भा0जी0बी0नि0 के पास 72 बैंक बीमा पार्टनर जुड़े हुए हैं। हमारे बीमा निगम ने 1956 से आज तक देश के आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में बढ़–चढ़ कर योगदान दिया है। अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में 184 करोड़ की पूंजी का योगदान दिया और 13वीं पंचवर्षीय योजना में यह बढ़कर 28,01,184 करोड़ पूंजी हो गया। आज भी LIC Fund का 80 प्रतिशत सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं और देश के बुनियादी ढांचे के सुधारों पर निवेश किया जाता हैं और एल.आई.सी. ने ऐजेन्ट भर्ती माध्यम से 13.5 लाख लोगों को जिस में महिलाऐं भी शामिल है को रोजगार प्रदान किया इन बीमा ऐजेन्टों ने भी जीवन बीमा को लधु बचत में प्रवर्तित करते हुए हमारे निगम के Slogan 'जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी' को और सार्थक बनाया है।

भारत सरकार की विनिवेश के प्रहार के बावजूद निजि कम्पनियों की मौजूदगी और कोरोना वायरस जैसी महामारी के बावजूद भा0जी0बी0 ने अपने नवव्यवसाय में लगातार बढ़ोतरी की है।

इसके बावजूद भारत सरकार द्वारा LIC IPO लाया गया। आज देश का सबसे बडा LIC IPO खुल चुका है। पहले दिन 67 प्रतिशत और दूसरे दिन 1.17 प्रतिशत लोगों द्वारा LIC IPO लिया गया और LIC IPO 949 रूपये पर खुला परन्तु IIPC के अनुसार LIC IPO 1300-1400 रूपये तक खुल सकता था अर्थात निवेशकों से प्रति शेयर 450 रूपये और अधिक लिये जा सकते थे। इस IPO के तहत भारत सरकार ने भा0जी0बी0 की 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा। पहले भारत सरकार की मंशा 5 प्रतिशत बेचने की थी परन्तु रूस-युक्रेन युद्ध के चलते एवं निवेशकों की और से कम मांग की आशंका के चलते भा0जी0बी0 की बेची जाने वाली हिस्सेदारी को घटाया गया। भारत सरकार की भा0जी0बी0 के प्रति इस प्रकार के नकारात्मक रवैया से क्या देश की सबसे बड़ी कम्पनी का वजूद इस प्रकार कब तक कायम रहेगा :-

किसी भी कम्पनी का Value of New Business Margin उसका प्रभावी मानदण्ड होता है। आज भा0जी0बी0 निगम का VNB 15 प्रतिशत और दूसरी ओर निजी बीमा कम्पनियों का VNB 30 प्रतिशत है जो कि हम बीमा कर्मियों के लिए गहन चिन्तन का विषय है। दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा Sick Units को भी लगातार पूंजी सहायता दिलाना जैसे अभी हाल ही में IDBI में 4743 करोड़ की पूंजी डलवाई गई, और State Electricity Board में 1200 करोड़ की पूंजी, Water Sewerage में 322 करोड़ की पूंजी का निवेश करवाया। यह कदम भा0जी0बी0 के लिए काफी जोखिम भरे है और उधर भारत सरकार LIC IPO लाकर पॉलीसिधारकों के विश्वास के साथ सरेआम धोखा कर रही है, जिसका हम बीमा कर्मियों ने पूरे देश में दो दिवसीय हड़ताल करके अपना, भारत सरकार के विरूद्ध रोष जताया क्योंकि हमारे महान संगठन AIIEA के अनुसार विनिवेश चाहे छोटा ही सही पर निजीकरण की दिशा में एक कदम है और हम बीमा कर्मी अपने संगठन के नेतृत्व में कई दशकों से भा0जी0बी0 के वजूद को बचाने में संघर्षरत हैं और संगठन का आहवान भी है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, हम बीमा कर्मियों को निरन्तर संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमारे महान संगठन का विश्वास भी है कि-'आन्दोलन हथियारों से नहीं हौंसलों से जीते जाते हैं।'

संगठन के इसी हौसले से हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस प्रकार से संगठन के मार्गदर्शन में

हमने पिछले संघर्षों में जीत हासिल की है इसी प्रकार हमारा संगठन अपनी दूरगामी सोच एवं संघर्ष के रास्ते LIC IPO को भी निरस्त कर देगा और हमें अपने महान संगठन एवं अपने बीमा उद्योग पर गर्व है, हम सभी बीमा कर्मी इनकी रक्षा के लिए सदैव वचनबद्ध हैं।

वेतन पुनरिक्षण-संगठन की शानदार उपलब्धि

15 अप्रेल 2021 का दिन AIIEA के संघर्षमय इतिहास मे सुनहरे अक्षरों मे अंकित हो गया जब संगठन ने हम बीमा कर्मियों के लिए अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों मे अब तक का सबसे बेहतर वेतन पुर्नरीक्षण हासिल किया। संगठन द्वारा 1.8.2017 से लागू 16 प्रतिशत बड़ौतरी के साथ हासिल किया गया वेतन पुर्नरीक्षण हमारे संस्थान के अत्यंत सुदृढ़ वित्तीय आधार के अनुरूप है और इस की भुगतान क्षमता को परिलिक्षित करता है।

शुरु से ही AIIEA का यह प्रयास रहा है कि वेतन पुर्नरीक्षण स्वतंत्र रुप सें, निगम की भुगतान क्षमता, प्रगति व हमारे उत्कृष्ट कार्य प्रर्दशन के हिसाब हों। बाहरी घटनाक्रम या अन्य वित्तीय संस्थानो का कोई भी नकारात्मक असर हमारे वेतन निर्धारण पर न हो अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि वर्तमान वेतन पुर्ननिर्धारण जैसा कि AIIEA ने कहा था कर्मचारियों की आंकाक्षाओं व अपेक्षाओं से बढ़ कर हुंआ है इस सबके लिय हम करनाल मण्डल की ओर से AIIEA नेतृत्व को इस शानदार उपलब्धि के लिय धन्यवाद करते है।

साथियों हमारा अगला Wage Revision 1.8.2022 से देय है जिसके लिए AIIEA ने अपनी रायपुर Working Comittee में Charter of Demands को पूरे हिन्दुस्तान के सभी साथियों से राय मश्वरा लेने के बाद Final किया व उसके उपरान्त 11 अगस्त 2022 को Lic Management को सौंप दिया और अवगत करवाया कि हमारे साथियों की अपेक्षाओ के अनुरुप अगला वेतन पुर्ननिवारण होना चाहिए।

हम इस सम्मेलन के माध्यम से यह विश्वास व्यक्त करते है कि हमारा 1.8.2022 से देय वेतन पुर्नरीक्षण भी हमेशा की भान्ति साथियों की अपेक्षाओं के अनुरुप शानदार होगा क्योंकि

AIIEA है तो सब सम्भव है।

मण्डल कमेटी की गतिविधियां

मण्डल कमेटी के रूप में कार्य करना व बहू आयामी भूमिका को सजग, सवेंदनशील, विचार धारात्मक व सभी के सहयोग से अपेक्षा पूर्ण निर्वहन करना हमेशा ही काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। एक ओर जहां संगठन के उच्च स्तर व नेतृत्व की मण्डल कमेटी से अपेक्षा रहती है कि सभी संगठनात्मक आहवानों व गतिविधियों का उच्च वरीयता पर संगठन की विचारधारा व रीति नीति के अनुरूप निष्पादन सुनिश्चित हो वही मण्डल कमेटी की अधीनस्थ शाखा कमेटियों व सभी साथियों की भी सदैव अभिलाषा रहती है कि मण्डल कमेटी उन की आशाओं के अनुरूप उनके विषयों का त्वरित निष्पादन निर्धारित करें। इस प्रकार मण्डल कमेटी संगठन के धरातलीय आधार व दृष्टिकोणात्मक नेतृत्व के बीच का अहम बिन्दु है। संगठन के स्तर पर कार्य करने हेतु आत्म विश्वास व प्रेरणा का प्रमुख आधार सदैव ही हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व रहता है। क्षेत्रीय नेतृत्व की कार्यप्रणाली, व्यवहार तथा मौखिक व लिखित मार्गदर्शन भी मण्डल कमेटी को उल्लेखनीय सांगठनिक योगदानों हेतू प्रेरित करते हैं। नेतृत्वकारिता हेतू आदर्श ऐसी कसौटियों पर खरा उतरने वाले व्यक्तित्व ही हमेशा अनुकरणीय व स्मरणीय रहते हैं।

हमें अपने क्षेत्रीय नेतृत्व से लगातार प्रेरणादायक व सहयोगात्मक व्यवहार मिला है। क्षेत्रीय नेतृत्व की कर्मचारियों व शाखाओं की समस्याओं व हमारे संगठन के विभिन्न विषयों के बारे में प्रभावी भूमिका रही है। क्षेत्रीय नेतृत्व की ओर से मण्डल कमेटी को हर सम्भव सहयोग व मार्गदर्शन मिला है, जिसके चलते आज हम यहां पहुचें हैं। नेतृत्व की वैज्ञानिक सोच व लोकतान्त्रिक मूल्यों में विश्वास के आधार पर कार्य करने की शैली ने साथियों में नई उर्जा का संचार किया है। हम इस सबके लिये आप सभी साथियों की ओर से क्षेत्रीय नेतृत्व को हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

हमारे मण्डल में हमारी शाखा समितियों के सहयोग से संगठन के सभी आहवान सफलतापूर्वक लागू किये जाते हैं। मण्डल समिति व शाखा समितियाँ एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हुए संगठन व संस्थान को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। AIIEA का इतिहास

संघर्षों व उपलब्धियों का हतिहास है। संगठन का मानना है कि आज तक की सभी उपलब्धियाँ सघन संघर्षों व जागरूकता का ही नतीजा है। हमारे मण्डल में AIIEA व NZIEA के सभी दिशा निर्देशों व आहवानों को शत प्रतिशत सफलता के साथ अंजाम दिया जाता है। अल्पकालिक सूचना पर भी सभी शाखाओं में संघर्ष के सारे कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ सफल बनाए जाते हैं। सभी जानकारियों की सूचना सभी साथियों को मिले, यह मण्डल कमेटी व शाखा सचिवों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। हमारे पिछले अधिवेशन से लेकर आज तक AIIEA व NZIEA के दिशा निर्देश में जो भी संघर्ष के कार्यक्रम आये उन्हें मण्डल में शत प्रतिशत पूरे जोश व उत्साह के साथ लागू किया गया, जिसमें मुख्य रूप से

8 जनवरी 2020 की अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित : केन्द्र में सत्तासीन मोदी सरकार की पूंजी परस्त व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ व नव उदारवाद की आत्मघाती नीतियों के विरोध में तथा मेहनत कश व आमजन से जुड़े मुददो के समर्थन मे देश के दस केन्द्रीय ट्रेड युनियनों AIIEA सहित बीमा, बैंक, रक्षा अन्य क्षेत्रो के संगढन, राज्य व केन्द्रीय कर्मचारी महासघों द्वारा किय गये आहवान के क्रम मे 8 जनवरी 2020 की हड़ताल अभूतपूर्व सफल रही ।

AIIEA के आहवान पर करनाल मण्डल मे भी हमारे साथियों ने इस हड़ताल के अवसर पर मण्डल कार्यालय करनाल, कैथल, पन्चकूला, कुरूक्षेत्र, जीन्द, नरवाना, जगाधरी, कालका, अम्बाला कैन्ट व अम्बाला सिटी सहित सभी केन्द्रो पर प्रभावी विरोध कार्यक्रम आयोजित किये। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हम बीमा कर्मियों को विमुख करने हेतू सोशल मीडिया सहित अनेक माध्यमो से भ्रमित करने के प्रयास किये गये लेकिन AIIEA के सिपाही टस से मस नही हुऐ व एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया।

04 फरवरी 2020 एक घन्टे की बर्हिगमन हड़ताल : 27-30 जनवरी, 2020 को विशाखापटनम में सम्पन्न AIIEA के 25वें रजत जयन्ती महाधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र भा0जी0बी0 का निजीकरण की दिशा में सरकार बजट में कोई भी कदम उठाती है तो देशभर के भा0जी0बी0 कर्मचारी विरोध प्रर्दशन व एक घण्टे की बर्हिगमन हड़ताल करेगें। संसद के पटल पर 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री द्वारा भा0जी0बी0 को शेयर बाजार में सूची बद्ध करने की घोषणा के साथ मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा - एन0डी0ए0 सरकार नग्न हो कर पूरी तरह अपने देश विरोधी, बीमा धारक विरोधी व जन विरोधी रंग में आ गई। अत: संगठन के निर्णयानुसार 3 फरवरी 2020 को द्वार प्रर्दशन व 4 फरवरी 2020 को एक घन्टे की बर्हिगमन हड़ताल का हमारे मण्डल में सफलता पूर्वक आयोजन किया गया।

26 नवम्बर 2020 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल : सरकार की जन विरोधी, मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के दस केन्द्रीय फैडरेशनों व ऐसोसिएशनों के आहवान पर 26 नवम्बर 2020 को की गई एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को व्यापक समर्थन मिला और हड़ताल की पूर्ण सफलता में एक नया इतिहास रच दिया। इस हड़ताल में 25 करोड़ मजदूरों व कर्मचारियों ने भागीदारी की हमारे देश के उदारीकरण के दौर की यह 20वीं हड़ताल थी। यह हड़ताल अब तक की 20 हड़तालों में सर्वाधिक व्यापक, कामयाब व सामंजस्यपूर्ण हड़ताल रही।

18 मार्च, 2021 की हड़ताल भारी सफलता के साथ सम्पन्न : भारतीय जीवन बीमा निगम में 18 मार्च, 2021 को ए0आई0आई0ई0ए0 सहित अधिकारियों व कर्मचारियों के श्रम संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने 18 मार्च 2021 को देशव्यापी हड़ताल की। इस हड़ताल का आयोजन आई0पी0ओ0 के माध्यम से भा0जी0बी0 को सूचीबद्ध करने, एफ0डी0आई0 की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने व सार्वजनिक क्षेत्र जनरल इन्शोरेंस कम्पनी का निजीकरण करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ व 01.08.2017 से देय वेतन पुर्णनिर्धारण के समझोते को अविलम्ब करने की मांग को स्वीकृत करने के लिये किया गया।

बीमा कर्मचारियों की इस हड़ताल ने राज्य सभा के अन्दर बीमा क्षेत्र में एफ0डी0आई0 की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किये जाने वाली बिल पर जारी बहस के समय ही अपना प्रतिरोध प्रतिबिंबित किया। सरकार की बेशर्मी यह है कि एफ0डी0आई0 की सीमा को 74 प्रतिशत करने वाला बीमा संशोधन बिल 2021 उसी दिन पास किया, जिस दिन भा0जी0बी0 नि0 में संगठन इसके विरोध में हड़ताल कर रहा था।

28, 29 मार्च 2022 राष्ट्रहित में दो दिवसीय अभूतपूर्व सफल हड़ताल : 28, 29 मार्च 2022 को दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आयोजन 10 केन्द्रीय श्रम संगठनों के आहवान पर किया गया। इस आह्वान के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने भी 10 दिवसीय ग्रामीण भारत बंद का

आयोजन किया।

नई पैंशन स्कीम के विरोध सहित अनेक मेहनत कश व आमजन के मुददो के लिए थी जिसमें देश भर के बीमा कर्मचारी करोड़ो मेहनत कशों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर दो दिवसीय देश व्यापी हड़ताल पर रहें। यह गर्व का विषय है कि तमाम नकारात्मक प्रचार व बीमा कर्मियो की एकता को तोड़ने के सभी प्रयासों को दर किनार करते हुऐ सभी साथियो ने अत्यन्त जोश व उत्साह के साथ अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयो पर आधारित इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुऐ 28-29 मार्च 2022 की हड़ताल को दिल्ली मण्डल1मे पूर्णतया कामयाब बनाया।

यह हड़ताल केन्द्र सरकार की विनाशकारी, जन विरोधी, निजीकरणवादी, पूंजीपरस्त नीतियों के खिलाफ थी।

04 मई 2022 : 4 मई 2022 को दो घन्टे की बहिर्गमन हड़ताल केन्द्र सरकार द्वारा अपनी नवउदारवादी नीतियों के तहत एल.आई.सी. का निजीकरण कर दूरगामी सोच के परिपेक्ष्य मे किये जा रहे इस के विनिवेश की कोशिशो का बीमा कर्मियों ने AIIEA के नेतृत्व मे जबरदस्त प्रतिरोध किया

आई.पी.ओ. के खोले जाने के दिन इस के विरोध मे अपना प्रतिरोध दर्ज कराने के उददेश्य से इस हड़ताल का आयोजन AIIEA द्वारा किया गया था 28-29 मार्च की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के तुरंत बाद ही की गई इस बहिर्गमन हड़ताल के द्वारा की गई प्रतिक्रिया का बीमा कर्मियो ने क्रान्तिकारी अभिनन्दन किया व इसे सफलतम हड़ताल बनाया। करनाल मण्डल कार्यालय सहित सभी शाखाओं मे हड़ताल पूर्णतया सफल रही।

उपरोक्त हडतालों के अलावा हमारे मण्डल मे निम्नलिखित संघर्ष के कार्यक्रम आयोजित किये गये।

27-30 जनवरी 2020 : विशाखापट्नम में आयोजित AIIEA के 25वें रजत जयन्ती महाधिवेशन में सक्रिय व उत्साहपूर्ण भागीदारी।

13 मार्च 2020 : अविलम्ब वेतन पुनरीक्षण हेतु वेतन वार्ताएँ शुरू किये जाने की मांग को लेकर द्वार सभा एवं विरोध प्रदर्शन।

16 मार्च 2020 : अविलम्ब वेतन पुनरीक्षण हेतु वेतन वार्ताएँ शुरू किये जाने की मांग में द्वार सभा

एवं विरोध प्रदर्शन।

03 जुलाई 2020 : केन्द्र सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों व एलआईसी के आईपीओ प्रस्ताव के विरूद्ध देशव्यापी प्रतिरोध दिवस का आयोजन, द्वार सभा, बैज धारण व प्रदर्शन।

09 अगस्त 2020 : सार्वजनिक क्षेत्र एलआईसी व जीआईसी को बचाओ दिवस का आयोजन, द्वार सभा एवं प्रदर्शन।

31 अगस्त 2020 : NZIEA के आह्वान पर एलआईसी को संरक्षित करो दिवस का आयोजन, द्वार सभा एवं प्रदर्शन।

23 सितम्बर 2020 : केन्द्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर केन्द्र सरकार की मजदूर विरोध नीतियों, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश प्रस्तावों के विरोध में भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन।

08 दिसम्बर 2020 : संयुक्त मंच के आह्वान पर एलआईसी में आई.पी.ओ. के प्रस्ताव के विरूद्ध व कर्मचारियों के मुददो तथा वेतन पुनरीक्षण हेतु भोजनवकाश के दौरान द्वार सभा एवं प्रदर्शन।

15 दिसम्बर 2020 : संयुक्त मंच के आह्वान पर एलआईसी में आई.पी.ओ. के प्रस्ताव के विरूद्ध व कर्मचारियों के मुददो तथा वेतन पुनरीक्षण हेतु बैज धारण, द्वार सभा एवं प्रदर्शन।

08 फरवरी 2021 : केन्दीय बजट में शामिल एलआईसी में एफडीआई सीमा बढ़ाने, जीआईसी कम्पनियों के निजीकरण की घोषणा व एलआईसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किये जाने की बजट घोषणा के विरूद्ध जोरदार प्रदर्शन।

08 मार्च 2021 : अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन।

15 अप्रेल 2021 : AIIEA के अनवरत प्रयासों से एलआईसी कमचारियों हेतु वेतन पुनरीक्षण हासिल। विशेष सभा का आयोजन।

09 अगस्त 2021 : केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश प्रस्तावों के विरोध में **भारत बचाओं दिवस** का आयोजन।

3 फरवरी 2022 : केन्द्र सरकार के बजट प्रावधान व LIC को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किये जाने की बजट घोषणा के विरूद्ध जोरदार प्रदर्शन।

08 मार्च 2022 : अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन।

अनुकम्पा आधारित नियुक्तियां

आलोच्य अवधि में यह दुख:द रहा कि हमारे कुछ साथी असमय काल कल्वित हो गये। निश्चित ही यह आघात संगठन व पीड़ित परिवारों के लिए अत्यन्त दुख:द व कष्टदायी था। इस अवसर पर संगठन ने अपने कर्तव्य के अनुरूप कार्य करते हुए उनके मृत्योपरान्त हित लाभों के भुगतान एवं उनके योग्य अश्रितों को अनुकम्पा आधार पर निगम में नियुक्ति हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रयास किये।

महिला उपसमिति की गतिविधियां

महिला साथियों की उत्साहवर्धक भागीदारी

हमारे मण्डल में संगठन के आहवान पर आयोजित सभी हड़ताल व प्रर्दशन कार्यक्रमों में हमारी महिला साथियों का बढ़ चढ़कर भागीदारी रही है। मण्डल कमेटी का हमेशा यही प्रयास रहा है कि सभी संगठनात्मक आयोजनों व संगठन की नेतृत्वकारिता में हमारे महिला साथियों की सक्रिय भागीदारी बढ़े व इस हेतू मण्डल कमेटी ने सदैव ही महिला साथियों को प्रोत्साहित भी किया है।

दिल्ली मंडल 1 कार्यालय महिला उप समिति ने साथी नीता सिंघल के नेतृत्व में अभूतपूर्व सामाजिक व संगठयिक कार्य किए हैं । मंडल कार्यालय में महिला दिवस के आयोजनों के अतिरिक्त विभिन्न आयोजनों के माध्यम से विभिन्न संस्थानों जैसे कि उत्थान अनाथ आश्रम से जो एक`वे संस्था है जहां ०-२ वर्ष के अनाथ बच्चों की देखभाल की जाती है। वहां उनकी आवश्यकता अनुसार सामग्री उपलब्ध कराना उपवन अनाथ आश्रम में जहां अनाथ बालिकाओं का पालन पोषण किया जाता है वहां भी उनकी जरूरतों के अनुसार सामग्री प्रदान की गई साथ ही साथ संगठन द्वारा विभिन्न संगठित कार्यक्रमों जैसे महाघसा, संसद पर प्रदर्शन एवं विभिन्न कन्वेंशंस में दिल्ली DO1 की महिलाएं साथियों ने हमेशा बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर संगठन को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

किसान आन्दोलन के साथ एक जुटता व आर्थिक सहयोग

NZIEA के निर्णयानुसार किसान संघर्ष को तन मन धन से सहयोग व समर्थन देने की दिशा में दिल्ली मण्डल की और से हर सम्भव प्रयास किया गया।

दिल्ली मण्डल की और से अखिल भारतीय किसान संभा को सहयोग राशि भेट की व संगठन के निर्णयानुसार 4 दिसम्बर 2020 को भोजन अवकाश मे गेट मीटिंग में मोदी सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों व किसान विरोधी कानूनों का कड़ा प्रतिरोध किया गया और किसान संघर्ष के साथ एक जुटता का प्रदर्शन किया

इसके अलावा कोरोना महामारी के समय भी करनाल मण्डल के साथी आर्थिक सहयोग मे भी पीछे नही रहें लॉकडाऊन के दौरान भी साथियों ने मण्डल कमेटी के खाते मे On-Line Transfer के माध्यम से आर्थिक सहयोग किया व मण्डल की तरफ से 1,35,185/- की राशि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के माध्यम से मुख्यमन्त्री राहत कोष मे जमा की।

संगठन

साथियों, संगठन अपनी ज़ायज मागों को हासिल करने, कर्मचारियों को बेहतरी के लिए उद्योग की बेहतरी के लिए, समाज मे एकता व समानता कायम करने के लिये एकजुट संघर्ष हेतू महत्वपूर्ण व मजबूत औजार है। और अधिवेशन ही वह सर्वाधिक उपयुक्त व सर्वोपरि मंच है जहाँ हमे आलोच्य अवधि का पूरी ईमानदारी के साथ सांगठनिक अवलोकन करके विगत अनुभवो से सबक लेकर भावी आधारो को निर्धारित करने तथा हमारी कार्य प्रणाली को और अधिक परिपक्व बनाने हेतू समुचित चिन्तन व निर्णयन का अवसर प्राप्त होता है।

यह हमारा व हमारे संस्थान का सौभाग्य है कि उसके कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व एक ऐसा संगठन करता है जिस की सोच, नीतियों व कार्य प्रणालियों में संस्थान के दीर्घ कालिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुऐ कर्मचारियों के हर प्रकार के हितो को समाहित करने का प्रयास किया जाता है। संगठन को मात्र स्थानान्तरण, पदौन्नति व पदस्थापना का ही साधन मानना उस के सैद्धान्तिक मूल उददेश्य से हटना होगा जो हमारे सामूहिक निहितार्थो को ही चोट पहुचायेगा तथा शोषण मुक्त व समतामूलक समाज की हमारी अवधारणा को कमजोर करेगा।

हमें गर्व है कि हमारा संगठन न केवल कर्मचारियों को मिल रहे लाभों व सुविधाओं को बनाये रखने में एवं उनमे निरन्तर वृद्धि करवाने में सफल हुआ है बल्कि विपरीत आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों में भी संस्थान को मजबूती प्रदान करते हुऐ निरन्तर प्रगति की राह पर अग्रसर है। पिछले तीन दशको से राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय दबाव के बावजूद निगम के मूल स्वरूप में अभी तक की सरकारे कोई परिवर्तन नही कर पाई इस का श्रेय A.I.I.E.A. को ही जाता है इतना ही नहीं देश के श्रमिक आन्दोलनो मे भी हम अपनी महत्वपूर्ण व नेतृत्वकारी भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रहे है।

साथियों मजबूत संगठन का कोई विकल्प नही होता जो सुविधायें, सुरक्षा व लाभ हम पा रहे है वे प्रबधन या सरकार को रहमदिली या कृपा के कारण नहीं बल्कि इस के पीछे संगठन की शक्ति, सक्रियता व सजगता के साथ हमारी सांगठनिक गतिविधियां रही है प्रंबधन व सरकार की हमारी प्रत्येक गतिविधि पर नजर रहती है। और हमारे प्रति उनके रवैये का निर्धारण हमारे कार्यक्रमों की सफलता व विफलता के अनुपात में ही तय होता है। जब हम संगठित हो कर संगठन शक्ति के रूप मे सरकार व प्रबधन के सामने खड़े होते है तो उन्हे न चाहते हुऐ भी हमारी मागों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है और प्रबधन व सरकार की हर सम्भव कोशिश होती है कि वे हमे साम दाम

दण्ड भेद द्वारा सांगठनिक रूप से कमजोर करे अपने इस कार्य के लिए कई बार वे ऐसे संगठनों का भी सहारा लेते है जो वजूदविहीन है कभी वे हमारे सदस्यों मे से कुछ को इस्तेमाल करने का असफल प्रयास भी करते है। इसलिए जरूरी है कि संगठन के सदस्य वैचारिक रूप से परिपक्व व मजबूत हो। लगातार हो रही सेवा-निवृर्ति और आवश्यक भर्ती की कमी के कारण हम संख्यात्मक रूप से सिकुड़ते जा रहे है ऐसे में सांगठनिक कार्यक्रमों तथा सघर्षो मे सदस्यों की शत-प्रतिशत भागीदारी जरूरी है अतः सभी सदस्यों के बीच मुददों पर निरन्तर संवाद व चर्चा अति आवश्यक है। शाखा स्तर से ले कर अखिल भारतीय स्तर तक हम संगठन को जितना अधिक मजबूत बनायेगे उतना ही हम सुरक्षित रहेगे। इस समझ को ध्यान में रखते हुऐ हमे अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रण लेना होगा हम साथियों को अक्सर यह कहते हुऐ पाते है कि संगठन कमजोर हो गया है सच्चाई तो यह है कि कमजोर संगठन नही, हम होते है मनुष्य मे स्वाभाविक प्रवृति है कि वह न तो अपनी कमजोरी बतलाना चाहता है न ही उस पर चर्चा करना चाहता है हमे अपनी कमजोरियों पर दृढ़ता से विजय पानी होगी जिस परिवेश मे हम रह रहे है उस के इर्द गिर्द क्या घट रहा है उस पर भी पैनी नजर रखनी होंगी। क्योकि हमारा स्वयं का घर तभी सुरक्षित रह पायेगा जब हम दूसरो के घरों को बचाने मे अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहेगें। अपने कार्यकाल मे हमने कुछ सागंठनिक कमजोरियों को महसूस किया है जिसकी चर्चा करना हम अपना कर्तव्य समझते है और साथियों से आह्वान करते है कि आज इस अधिवेशन के माध्यम से हम यह प्रण ले कि अतिशीघ्र हम इन कमजोरियों को दूर करें।

- कुछ साथी व शाखाऐं संगठन के आहवानो को गम्भीरता से नही लेते।
- महिला व युवा साथी संगठन की जिम्मेदारी लेने से झिझकते है।
- संगठन के आह्वान पर की जाने वाली रैली, भोजनावकाश प्रदर्शन, हड़ताल मे उपस्थिति उस अनुपात मे नही होती जो होनी चाहिये
- हाल के वर्षो मे देखा गया है कि हमारे साथी हड़ताल से बचने के लिय अवकाश पर चले जाते है जो हमारे संघर्ष को कमजोर करता है।
- संगठन के पत्र पत्रिकाओं व साहित्य को पढ़ने व साथियों के बीच चर्चा करने मे हमारे संगठन के पदाधिकारी व सदस्य वांछित रूचि नही रखते।
- विभिन्न मुददो पर शाखा व मण्डल स्तर पर आयोजित की जाने वाली सभाओं मे हिस्सेदारी के प्रति साथी गंभीर नही होते

- लेवी व विभिन्न आर्थिक योगदान से सदस्य बचने की कोशिश करते है।

जबकि आज के हालात मे संगठन का हित हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहियें। संकीर्ण निजी हितो व व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का परित्याग कर सामूहिक हित व उददेश्य को महत्व देना व संगठन को मजबूती प्रदान करना हमारा एक मात्र ध्येय होना चाहिये कोई भी संगठन तभी मजबूत हो सकता है जब सदस्य इसे बल प्रदान करे। शाखा स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक जितना हम इसे मजबूत बनायेगें। उतनी ही अधिक सुविधायें व सुरक्षा हासिल करने मे हम कामयाब होगें हमे अपनी कमजोरियों को दूर कर संगठन को प्रत्येक स्तर पर और अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना होगा।

संगठन के संविधान मे शाखा समिति, मण्डल समिति व जोनल नेतृत्व के कार्यकलाप स्पष्ट रूप से परिभाषित है। जो इस की शक्ति का आधार है। यहां तक कि प्रत्येक साथी व पदाधिकारी के कर्तव्य व अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित है। कुछ साथी व पदाधिकारी कई बार निजी स्वार्थवश अनुशासन की सीमाओं को लाघं जाते है। संगठन मे मनमाने आचरण का कोई स्थान नही है।

मण्डल मे हर स्तर पर हमने पूरे अनुशासन के साथ हर जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास किया है। साथियों का अपेक्षित सक्रिय सहयोग भी हमें हर समय प्राप्त हुआ है। महिला साथियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। हमने अपने पिछले समय की अपनी कई कमियों व कमजोरियों पर काबू पाया है इस पर हम जहां सन्तोष व्यक्त करते है वहीं दूसरी और हम आहवान करते है कि इस स्थिति को बरकरार रखना भी आने वाले समय मे हमारे लिये एक चुनौती हो सकती है हमे यही नही रूकना है हमे चलते ही रहना है। संगठन एक निरन्तर प्रक्रिया हैं संगठन को मजबूत क्रियाशील व जागरूक बनाने के लिय शिथिलता एवं निजी स्वार्थो को त्याग कर समय के अनुकूल हमे उन सभी कदमो को उठाना है। जिससे कि हम आगे बढ़ सके। सशक्त संगठन ही हमारे अस्तित्व की गारंटी हैं आज AIIEA ही हमारी आशा व आकांक्षा पूर्ति का एक मात्र साधन है। निगम के आई0पी0ओ0 के बाद परिस्थितियां इतनी सहज नही होगी क्योकि निगम मे प्रबन्धकीय स्तर पर भी नये-नये बदलाव होगें ऐसे मे हमारी संगठन शक्ति ही हमारा सुरक्षा कवच है।

यह अखण्ड सत्य है कि सामाजिक न्याय का संघर्ष अकेले नही लड़ा जा सकता अतः देश की आर्थिक सम्प्रभुता की रक्षा के सामूहिक संघर्षो के साथ जुड़ कर कार्य करना होगा। हमारे आन्दोलनों ने जन भागीदारी ही हमारी सफलता तय करेगी अतः जन जागरण व चेतना पैदा करने के

लिए संगठन के आहवानों की शत-प्रतिशत सफलता हमे सुनिश्चित करनी होगी। संस्थान की सुरक्षा, बीमा धारको को बेहतर सेवा व निगम की प्रगति के साथ ही AIIEA की मान्यता व आगामी वेतन पुर्नरीक्षण, अपनी अपेक्षा अनुरूप हासिल करना आदि हमारी भावी जिम्मेदारियां होगी जिसे हम वैचारिक दृष्टि से सुदृढ़ व भावनात्मक रूप से मजबूत व एक जुट संगठनात्मक शक्ति से ही हासिल कर पायेगें। यह कार्य कठिन है लेकिन नामुमकिन नही।

हम लड़ेगे-जरूर लड़ेगे व निश्चित रूप से जीतेगें।
इस जुल्म के साये मे जुबां खोलेगा कौन
हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन

कान्तिकारी अभिवादन सहित
इन्कलाब जिन्दाबाद
AIIEA जिन्दाबाद
NZIEA जिन्दाबाद
कार्यकारिणी की ओर से

राहुल कौशिक
मण्डल सचिव
द्वारा दिल्ली मंडल समिति 1
की ओर से प्रस्तुत